

वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023

प्रलिस के लिये:

[वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [वन संरक्षण नियम](#), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980

मेन्स के लिये:

वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वन \(संरक्षण\) संशोधन अधिनियम 2023](#) लोकसभा द्वारा पारित किया गया जिसका उद्देश्य [वन \(संरक्षण\) अधिनियम, 1980](#) में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। यह भारत में वनों के संरक्षण के लिये एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून है।

पृष्ठभूमि:

- स्वतंत्रता के बाद वन भूमि के विशाल क्षेत्रों को **आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में नामित** किया गया था।
 - हालाँकि अनेक **वन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया** था तथा बना किसी स्थायी वन वाले क्षेत्रों को 'वन' भूमि में शामिल किया गया था।
- वर्ष 1996 के गोदावरमन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया** और फैसला सुनाया कि वन संरक्षण अधिनियम उन सभी भूखंडों पर लागू होगा जो या तो 'वन' के रूप में दर्ज थे या फिर शब्दकोश द्वारा परिभाषित **वन** के अर्थ से मलिते जुलते हों।
- सरकार ने **जून 2022 में वन संरक्षण नियमों** में कुछ बदलाव किया, ताकि डेवलपर्स को "ऐसी भूमि, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है", पर वृक्षारोपण करने की अनुमति दी जा सके और प्रतिपूरक वनीकरण की बाद की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे भूखंडों की अदला-बदली की जा सके।

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान:

- अधिनियम का दायरा:**
 - एक **प्रस्तावना शामिल करके** यह अधिनियम अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाता है।
 - इसके प्रावधानों की क्षमता को दर्शाने के लिये इस अधिनियम का नाम बदलकर **वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980** कर दिया गया।
- वभिन्न भूमियों पर प्रयोज्यता:**
 - यह अधिनियम, जिस शुरु में सरिफ **अधिसूचित वन भूमि** पर लागू किया गया था, बाद में **राजस्व वन भूमि और सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि** तक बढ़ा दिया गया।
 - संशोधनों का उद्देश्य **दर्ज वन भूमि, नजी वन भूमि, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना है।**
- छूट:**
 - अधिनियम में वनों के बाहर **वनीकरण** तथा वृक्षारोपण को **प्रोत्साहित करने के लिये कुछ छूट** का प्रस्ताव है।
 - सड़कों और रेलवे के किनारे स्थित बस्तियों एवं प्रतिष्ठानों के लिये कनेक्टविटी प्रदान करने हेतु **0.10 हेक्टेयर वन भूमि का प्रस्ताव** किया गया है, सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढाँचे के लिये **10 हेक्टेयर तक भूमि का प्रस्ताव** किया गया है तथा सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिये वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में **5 हेक्टेयर तक वन भूमि का प्रस्ताव** दिया गया है।
 - इन छूटों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, **वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC), नियंत्रण रेखा (Line of Control- LoC)** आदि के 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित **रणनीतिक परियोजनाएँ** शामिल हैं।
- विकास के लिये प्रावधान:**
 - अधिनियम नजी संस्थाओं को पट्टे पर वन भूमि के आवंटन से संबंधित **मूल अधिनियम** के मौजूदा प्रावधानों को सरकारी कंपनियों तक भी **वसितारित करता है।**

- इससे विकास परियोजनाओं को सुवधि मलिंगी और अधनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चिती होगी ।
- **नवीन वानकिी गतविधिधियों:**
 - संशोधनों में वनों के संरक्षण के लिये वानकिी गतविधिधियों की शृंखला में अग्रमि पंक्ती के वन कर्मचारियों के लिये बुनयिदी ढाँचे, इकोटूरज्मि चड्डियाघर और सफारी जैसी नई गतविधिधियों को जोडा गया है । वन कषेत्रों में सर्वेक्षण एवं जाँच को गैर-वानकिी गतविधिधियों नहीं माना जाएगा ।
- **जलवायु परविरतन शमन एवं संरक्षण:**
 - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चिती करना है कि ऐसे कषेत्र वन संरक्षण परयासों के पहचाने गए भाग के रूप में जलवायु परविरतन से नपिटने में भारत के परयासों में योगदान देना तथा वर्ष 2070 तक **नेट शून्य उत्सर्जन** जैसी भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतबिद्धताओं में योगदान देना ।
- **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:**
 - वधियक चड्डियाघरों, सफारी और इकोटूरज्मि की स्थापना जैसी गतविधिधियों को प्रोत्साहित करता है, जनिका स्वामित्व सरकार के पास होगा, साथ ही यह संरक्षित कषेत्रों के बाहर अनुमोदति योजनाओं में स्थापति कयिा जाएगा ।
 - ये गतविधिधियों न केवल वन संरक्षण तथा वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं बल्कस्थानीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसर भी उत्पन्न करती हैं, उन्हें समग्र विकास के साथ एकीकृत करती हैं ।

वधियक से संबंधति चतिाएँ

- **हदिी नाम पर आपत्तति:**
 - अधनियम के नए नाम (जो अब हदिी में है) पर इस आधार पर आपत्ततियाँ थी कयिह "गैर-समावेशी" था और इसमें दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर दोनों में "गैर-हदिी भाषी) आबादी के कई व्यक्ती शामिल नहीं थे ।"
- **पारस्थितिकि रूप से संवेदनशील कषेत्रों पर प्रभाव:**
 - वधियक में प्रस्तावति छूट ने वशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास रणनीतिक परयोजनाओं से संबंधति, पारस्थितिकि रूप से संवेदनशील कषेत्रों जैसे- हिमालय, ट्रांस-हिमालयी और पूर्वोत्तर कषेत्रों में नरिवनीकरण के बारे में चतिाएँ बढ़ा दी हैं ।
 - वधियक, 2023 (FCA) भारत की सीमाओं पर रहने वाले स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को समाप्त कर देगा ।
 - उचित "मूल्यांकन और शमन योजनाओं" के बिना, ऐसी मंजूरी से जैव वविधिता को खतरा हो सकता है और वषिम मौसम की घटनाओं को ट्रगिर कयिा जा सकता है ।
- **सीमति प्रयोज्यता:**
 - वधियक कानून के दायरे को केवल अक्टूबर 1980 या उसके बाद वन के रूप में दर्ज कषेत्रों तक सीमति रखता है । इस बहषिकरण के परिणामस्वरूप वन भूमि और जैव वविधिता वाले गरम स्थानों के महत्त्वपूर्ण हसिसे अधनियम के दायरे से बाहर हो सकते हैं, जसिसे उन्हें गैर-वानकिी उद्देश्यों के लिये संभावति रूप से बेचने, परविरतति करने, साफ करने तथा शोषण करने की अनुमति मिलि जाएगी ।
- **समवर्ती सूची और केंद्र-राज्य संतुलन:**
 - कुछ राज्य सरकारों ने तर्क दयिा है कविन संरक्षण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जसिका अर्थ है कडिस मामले में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है ।
 - उनका मानना है कि प्रस्तावति संशोधनों से संतुलन केंद्र की ओर झुक सकता है और वन संरक्षण मामलों में राज्य सरकारों के अधिकारों पर असर पड सकता है ।

आगे की राह

- प्रस्तावति संशोधनों और वनों, जैव वविधिता तथा स्थानीय समुदायों पर उनके संभावति प्रभावों का गहन एवं व्यापक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ।
- इस मूल्यांकन में पारस्थितिकि, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर वचिार कयिा जाना चाहयिे तथा इसमें वशेषज्जों, गैर-सरकारी संगठनों, आदविसी समुदायों और राज्य सरकारों सहति वभिन्नि हतिधारकों का योगदान होना चाहयिे ।
- सभी हतिधारकों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी चतिाओं को दूर करने के लिये उनके साथ सार्थक परामर्श एवं संवाद जारी रखना । इससे पारदर्शति, समावेशति और बेहतर नरिणय लेने में मदद मलिंगी ।

स्रोत : पी.आई.बी.